भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

COMMUNIST PARTY OF INDIA (MAOIST)

ओड़िशा राज्य कमेटी

ODISHA STATE COMMITTEE

प्रेस स्टेटमेंट **दिनांक : 8 मार्च 2014**

झुठे लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करो!

चुनावों से जनता की मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता

सच्चे जनवाद के लिए माओवादी जनयुध्द की राह चुनो!

प्यारी जनता

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में चुनावी नाटक शुरु हो गया है. चुनाव आयोग ने 9 चरणों में लोकसभा व ओड़िशा सहित तीन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है. रंग-बिरंगी टोपियों वाली पार्टियां, जो पांच साल तक लूट करने में मस्त रही अब फिर आपके सामने हाथ जोड़ कर आना शुरु कर दी हैं. पिछली बार प्रति उम्मीद्वार 40 लाख खर्च करने की अनुमति थी अब कि बार 70 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति दे दी है. पिछले चुनावों के नाटक पर 15,000 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे. इस बार भी जनता के खून पसीने की गाढी कमाई पानी की तरह बहायी जायेगी.

हमारी पार्टी नक्सलबाड़ी के समय से ही कहती आई है कि संसद केवल और केवल गुंडों का अखाड़ा है, और यह सच समय-समय पर सबित होता आया है. सच्चाई यही है कि भारत में बुर्जुआ जनवादी क्रांति सफल नहीं हुई और भारत की 'संसदीय व्यवस्था' ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा थोपी गयी संसदीय व्यवस्था है न कि जनवादी क्रांति का फल ! 1947 के बाद से भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद सहित अन्यन्य साम्राज्यवादियों के लिए नव उपनिवेशिक व्यवस्था के तहत लूट का स्रोत बन गया है.

भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला 1 लाख 76 हजार, कोयला खदान घोटाला 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपये, और कॉमन वेल्थ खेल घोटाला 60 हजार करोड़ रुपये, कुल मिलाकर देखा जाये तो आए दिन एक नया घोटाला सामने आता रहा है. वहीं कांग्रेस राग अलाप रही है 'हो रहा भारत निर्माण'! दरअसल कांग्रेस ने भारत का निर्माण नहीं बल्कि पूंजीपतियों का निर्माण किया है. विकास के नाम पर 400 से ज्यादा विशेष आर्थिक जोनों को मंजूरी दी गयी, जिससे लाखों एकड़ भूमि किसानों की छीन ली, खदानों व बड़े बांधों के निर्माण के लिए हजारों आदिवासियों की जमीनों, जंगलों को बर्बाद किया जा चुका है. जब किसान, आदिवासी अपने जल-जंगल-जमीन के लिए जीवन मरण के संघर्ष पर उतारु हो गए तो उसको भटकाने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून आदि लेकर आए. जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया, सरकार से जवाब मांगे जाने लगे तो उस गुस्से को ठंडा करने के लिए सूचना का अधिकार लाए. मनरेगा नाम से रोजगार गारंटी स्कीम चला रहे हैं और किसानों को उजाड़ कर, उन्हें मजदूर बना रहे हैं दस साल में ये कानून, वो कानून जो कांग्रेस बता रही है, सबके सब इस शोषक व्यवस्था को बचाने के लिए ही लाए गए कानून हैं. देश का विकास नहीं विनाश किया गया है. विकास दर 4.8 पर आकर गिर गयी है. मजदूरों, कर्मचारियों को बेरोजगार बना दिया गया है. छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं. बड़े कारखानों में लगातार छंटनी जारी हैं. जिससे लाखों मजदूरों को रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है. खुदरा व्यापारियों के पेट पर ठोकर मारते हुए खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश को लागू कर दिया है. महिलाओं से सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, देश की राजधानी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित जगह है. इसका कारण है साम्राज्यवादियों की नई आर्थिक नीतियों के तहत पश्चिम संस्कृति को भी शासक वर्गों ने आयात किया है. कृषि लगातर घाटे का सौदा बनती जा रही है क्योंकि सरकार ने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर दी है, लगातार खाद, बीज व किटनाशाको के रेट बढ़ाये जा रहे हैं. कृषि क्षेत्र के बजट में हर बार कटौती की जा रही है, जिसके कारण 2 लाख 96 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं. लेकिन दूसरी तरफ रक्षा बजट बढाया जा रहा. देश का सैनिकीकरण किया जा रहा है. करोड़ों किसानों के लिए कुछ करोड़ रुपयों का, तो मात्र कुछ लाख की सेना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये बजट का आवंटन किया जाता है. यूपीए सरकार साम्राज्यवाद परस्त एलपीजी नीतियों को लागू कर रही है, जनता उसके विरोध में उतरने से उस पर फासीवादी दमन चलाया जा रहा है.राहुल गांधी का गैस का नाटक सबके सामने है. पहले 12 सिलेंडर ही दिये जाते थे, लेकिन 2013 बजट में घटा कर 6 सिलेंडर कर दिये गए. अभी चुनावों को देखते हुए फिर 12 सिलेंडर दिये जाने की घोषणा की गयी है. इसके लिए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी 'प्रधानमंत्री पर गर्जे'! यह केवल जनता को लुभाने का नाटक है.

भाजपा आज एक फासीवादी हत्यारे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीद्वार घोषित कर जर्रा भी नहीं शरमा रही है. वह प्रचार कर रही है कि वह गुजरात मॉडल की तर्ज पर देश का विकास करेगी. गुजरात में 2000 से ज्यादा मुस्लमानों का कत्ल बीजेपी, आरएसएस, बजरंगदल जैसे संगठनों द्वारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया. गुजरात और ओड़िशा में भाजपा व अन्य भगवा आतंकवादी संगठनों द्वारा इसाइयों, दलितों पर हमले किये गए. नवीन पटनायक की भी इसमें मूकसहमति थी. क्या यही गुजरात मॉडल है. गुजरात में जनता का नहीं बल्कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे पूंजीपतियों का विकास हुआ है. हजारों किसानों की जमीनों को पूंजीपतियों को सौंप दिया गया है.जनप्रतिरोध की आवाज का कोई समाचार नहीं बनने दिया जाता. अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनता है इस से कोई बुनियादी बदलाव भारत में नहीं आने वाला.

दरअसल मनमोहन सिंग 1991 से जिन नीतियों को आगे बढ़ाया, नरेंद्र मोदी गुजरात में उन्हीं नीतियों को लागू किया है. वह नीतियां है उदारीकरण, नीजिकरण व भूमंडलीकरण की यानि देश की तमाम संपत्ति को दलाल पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों को सौंप दो. इन नीतियों को लागू करने में कांग्रेस व भाजापा के मोदी में कोई फर्क नहीं है.

नरेंद्र मोदी एक और नारा उच्छाल रहा है कि वह काले धन को स्विस बैंकों से वापस लायेगा. क्या जब बीजेपी सरकार में थी, तब उसे स्विस बैंकों का पता-ठीकाना नहीं मालूम था? गुजरात के नेताओं, पूंजीपतियों का काला धन क्यों अब तक वह स्विस बैंकों से नहीं निकलवाया जबकि 15 साल हो गये उसे मुख्यमंत्री बने. इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं लेकिन उसकी पार्टी भी,10 सालों तक इस मामले पर कुछ भी नहीं की. यह चुनावी स्टंट मात्र है.

'गुजरात मॉडल', स्विस बैंकों से पैसा लाने और रक्षा पर खर्च बढ़ाने के नारे सिर्फ मध्यम वर्ग को आर्किषत करने वाले हैं, इस से देश की 90 प्रतिशत मजदूर-किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला.

हर चुनावी मौसम की तरह इस बार भी तीसरा फ्रंट के रूप में सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एआईडीएमके आदि संभावनायें तलाश रहे हैं. तीसरा फ्रंट भी कांग्रेस–भाजपा से अलग हो ऐसी कोई बात नहीं है. सब पार्टियां अवसरवादी हैं. कौन कब पल्टी मारें कोई कह नहीं सकता. तमाम चुनावी पार्टियों का एक ही लक्ष्य है देश को कैसे लूटना है, जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है. अपने-अपने राज्यों में ये तमाम पार्टियां विदेशी कंपनियों को बुलाती हैं, लूटवाती हैं.

नवीन पटनायक की बीजू जनता दल 15 सालों से ओड़िशा में फासीवादी सत्ता चला रही है. इस ने दलाल पूंजीपतियों व विदेशी कंपनियों से समझौते कर सारी खनिज व वन संपदा को बेच दिया है. ओड़िशा को व ओड़िशा की जनता को पूरी तरह कंगाल बनाकर भूखमरी, गरीबी की दलदल में धकेल दिया है. विस्थापन, पलायान व भूखमरी ओड़िशा की पहचान बन गयी है.

अब की बार भारतीय चुनावों में अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी मीडिया में छाई हुई है. केजरीवाल अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ योध्दा के रुप में पेश कर रहा है. अरविंद केजरीवाल भ्रष्टचार के खिलाफ जनता के गुस्से को भुना कर सत्ता में आना चाहता है. अरविंद केजरीवाल इस व्यवस्था को बदलने की बात नहीं करता. जिस संसद की नीव भ्रष्टाचार, लूट व शोषण पर टीकी हो वह उस पर कैसे भ्रष्टाचारविहीन इमारत का निर्माण कसर सकता? अरविंद केजरीवाल जो मीठे सपने दिखा रहा है, जो वायदे कर रहा है वह छलावा है, उस धोखे में जनता को नहीं फंसना चाहिए. आने वाले समय में पता लग जाये गा कि वह साम्राज्यवाद, सामंतवाद व बड़े पूंजीपतियों के हित में काम करेगा या जनता के हित में!

संसदीय चुनावों से जनता का विश्वास धीरे-धीरे घटता गया. जनता ने चुनावों में भाग लेना ही छोड़ दिया. परिणाम स्वरुप पचास प्रतिशत से भी कम मतदान होता था. इस लोकतंत्र के मुखोटे को बचाने के लिए, और कुछ प्रगतिशील शक्तियां जीते हुए उम्मीद्वार को वापस बुलाने के अधिकार के लिए लड़ रही थीं. वहीं संघर्षरत इलाकों की जनता ने तो सिरे से ही इन चुनावों को खारिज कर चुनावों के बहिष्कार का नारा बुलंद किया हुआ है. जनता के उठते विश्वास को फिर से कायम करने के लिए, जनता की चुनावों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए नोटा बटन को सुर्पीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने मशीनों में लगाया है. नोटा बटन पूरी तरह से शक्तिहीन है क्योंकि जीतने वाले उम्मीद्वार से ज्यादा वोट भी नोटा बटन पर गिर जायें तो वहां के चुनाव रद्द नहीं होते न ही वह उम्मीद्वार हारा हुआ माना जाता. कुल मिलाकर यह जनता को गुमराह करने वाला बटन है और कुछ नहीं!

देश की मुक्ति के लिए, अपने जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए माओवादी पार्टी के नेतृत्व में देश की जनता, खासकर आदिवासी जनता संघर्ष कर रही है. इस संघर्ष की बदौलत उसने कई विदेशी व बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों की लूट को रोक दिया है. बैलाडिला से लोह अयस्क लूट कर लेजाया जा रहा है, रावघाट खदान खोलने के लिए, हजारों बीएसएफ को लगाकर रेल लाईन का निर्माण किया जा रहा है. पोस्को, टाटा, बिरला, वेदांता, अंबानी, जिंदल आदि के साथ केंद्र व रज्य सरकारों ने कई एमओयू साइन कर रखे हैं. माओवादी पार्टी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गयी है, क्योंकि उनकी लूट नहीं चलने देती. इसलिए शोषक-शासक वर्गों ने आपरेशन ग्रीनहंट की दमन शुरुआत की कांग्रेस हो या बजेपी, जनता दल हो या एनसीपी, ममता बैनर्जी हो या माकपा-भाकपा सभी ग्रीनहंट के नाम पर देश की अपनी ही जनता पर युध्द छेड़ने के लिए एकजुट हैं. कोई भी पार्टी जो चुनावों में खड़ी है इस अन्यायपूर्ण युध्द का विरोध नहीं करती. अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए अपने ही देश की सेना, पुलिस, अर्ध सैनिक बलों को उतारा जा रहा है, सैकड़ों गांव तबाह करा दिये जा चुके हैं, दर्जनों महिलाओं से बलत्कार किये जा चुके हैं, एड़समेट्टा, सार्केगुड़ा, से लेकर नियमगिरी, लांजीगढ़, गंदमर्धन, लालगढ़, सोनाबेड़ा, मैनपुर, उदंती सब जगह दमन का तांडव जारी है.

अगर देश को सही जनवाद, मुक्ति और विकास चाहिए तो वह दंडकारण्य, बिहार-झारखंड के रास्ते से ही हो सकता है. माओवादी पार्टी जनता से वायदा करती है कि नवजनवादी क्रांति की सफलता के बाद वह विदेशी कपंनियों, बड़े पूंजीपतियों की सारी संपत्ति छीन कर देश की जनता की संपत्ति घोषित कर देगी. विदेशों के सारे कर्जे रद्द कर देगी और हर जोतने वाले को जमीन की व्यवस्था करेगी.

हमारा आव्हान है कि चुनावी वायदों की मीठी गोली में छीपे जहर को पहचानिये, देश के गद्दारों, देश को बेच कर खाने वालों को अपने इलाके से मार भागाइये.

इसलिए मजदूर-किसानों, छात्र-बुध्दिजीवियों, दुकानदार-कर्मचारियों, महिलाओं सहित देश की सारी जनता से हमारी पार्टी आव्हान करती है कि इन झूठे लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करे और देश की मुक्ति के लिए, देश को साम्राज्यवाद, समांतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के पंजों से छुड़वाने के लिए माओवाद की राह चुने. पीएलजीए में भर्ती होकर नवजनवादी क्रांति की सफलता के लिए संघर्ष करे!

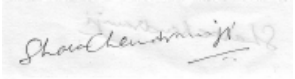

शरतचंद्र मांझी
प्रवक्ता
ओड़िशा राज्य कमेटी